



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 21 अप्रैल, 2005 / 1 वैशाख, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

शिमला-171002, 12 अप्रैल, 2005

संख्या एच०पी०ई०आर०सी०/सचिव/151/2005.—निम्नलिखित प्रारूप विनियम, जिन्हें हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, दिनांक 14 जनवरी, 2005 में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 2005 में संशोधन करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (36 का 2003) की धारा 181 की उप-धारा (2) के खण्ड (छ), (यछ) तथा (यठ) तथा धारा 86 की उप-धारा (1) के खण्ड (छ) के साथ पठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (10 का 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करता है, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 181 की उप-धारा (3) द्वारा यथोपेक्षित के अनुसार उनसे आम प्रभावित होने वाले व्यक्ति की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और एतद्वारा यह नोटिस (सूचना) दिया

ता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर, इनके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से तीस (30) दिन के अवसान पर किसी भी आक्षेप या सुझाव सहित, जो इस बावत उक्त अवधि के भीतर प्राप्त हुआ हो/हुए हों, विचार किया जाएगा।

इस निमित्त आक्षेप या सुझाव सचिव, हिमाचल प्रदेश, विद्युत विनियामक आयोग, क्यॉथल कमर्शियल काम्पलेक्स, खलिनी, शिमला को सम्बोधित किए जाने चाहिए :-

### प्रारूप विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2005 है।

(2) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम 49 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 2005 के विनियम 49 में,—

(क) विद्यमान विनियम को उप-विनियम (1) के रूप में संख्यायित किया जाएगा तथा उस के उपरान्त निम्न स्पष्टिकरण जोड़ा जाएगा, नामतः :-

“स्पष्टिकरण.—इस विनियम के प्रायोजन हेतु “उत्पादन कम्पनी” में सरकार, जो किसी अनुबन्ध के अधीन किसी उत्पादन कम्पनी से या तो उक्त कम्पनी में शेयर धारण करने के कारण या उस से जल/तटवर्ती या भूमि या भूमि में अधिकारों के उपयोग के बदले में उत्पादित विद्युत में प्रतिशतता के रूप में स्वामित्व (रायल्टी) लेने की हकदार है भी सम्मिलित है तथा वह उस हद तक उक्त उत्पादन कम्पनी में साधारण शेयर धारक समझी जाएगी।”;

(ख) निम्न उप-विनियम (2) जोड़ा जाएगा, नामतः :-

“(2) आयोग, अधिनियम की धारा 62 के अधीन टैरिफ अवधारित करते हुए, उपविनियम (1) के अधीन उत्पादन कम्पनियों और आवद्ध उत्पादन केन्द्रों द्वारा दिए गए तकनीकी ब्यौरे पर भी विचार करेगा, तथा इस प्रकार से अवधारित टैरिफ सरकार को, जो जल/तटवर्ती या भूमि या भूमि में अधिकारों के उपयोग के बदले में स्वामित्व (रायल्टी) लेने की हकदार है या शेयर धारक है, स्वयंमेव लागू होगा।”

आयोग के आदेश द्वारा

हस्ताक्षरित /—  
सचिव।

**AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT**

**HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION  
SHIMLA**

**NOTIFICATION**

*Dated, Shimla, the 11th April, 2005*

**No. HPERC/SECY/151/2005.**—The following draft regulations, which the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission proposes to make to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2005, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary), dated 14<sup>th</sup> January, 2005 in exercise of the powers conferred by clauses (g), (zg) and (zl) of sub-regulation (2) of section 181 and clause (g) of sub-clause (1) of section 86 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and all the powers enabling it in this behalf are hereby published as required by sub-section (3) of section 181 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Regulatory Commission, Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla-171002.

**DRAFT REGULATIONS**

**1. Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) (First Amendment) Regulations, 2005.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

**2. Amendment of regulation 49.**—In regulation 49 of the Himachal Pradesh

**Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2005,—**

- (a) existing regulation shall be numbered as sub-regulation (1) and thereafter following Explanation, shall be added, namely :—

“**Explanation.**—For the purposes of this regulation the expression “the Generating Company” shall include the Government, which under an agreement, is receiving or is entitled to receive, in the form of percentage of power generated by a company either on account of having a share in the said company or by way of royalty, in lieu of water/riparian usage or usage of land or rights thereunder; and the Government to the extent of the said royalty or share shall be deemed to be an equity partner in the aforesaid company.”; and

- (b) the following sub-regulation (2) shall be added, namely :—

“(2) The Commission shall, while determining the tariff under section 62 of the Act, also take into consideration the technical details submitted by the generating companies and the captive generating stations and the tariff so determined shall ipso-facto apply to the Government entitled to the share or royalty in lieu of water/riparian usage or usage of land or rights thereunder”.

**By order of the Commission**

*Sd/-*  
**Secretary.**